भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1207
उत्तर देने की तारीख 14 दिसम्बर, 2022

आत्मनिर्भर भारत योजना

1207. श्री कृपानाथ मल्लाह; श्रीमती जसकौर मीना; डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योजना की विशेषताएं क्या हैं;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान असम, राजस्थान और तमिलनाडु में इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत, आबंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;
(ग) निर्धारित लक्ष्य और अब तक प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत देश में 5जी ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क के विकास पर विचार कर रही है; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार राज्य मंत्री
(श्री देवुसिंह चौहान)

(क) आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत दूरसंचार विभाग का लक्ष्य अनुसंधान और विकास के लिए पारिस्थितिकी -तंत्र को बढ़ावा देने और प्रौद्योगिकियों के विकास में भारत को वैश्विक केंद्र बनाने तथा कोर ट्रांसमिशन उपकरण, 4जी/5जी नेक्स्ट जेनेरेशन रेडियो एक्सेस नेटवर्क और वायरलेस उपकरण, एक्सेस और कस्टमर प्रिमाइसेस इक्विपमेंट (सीपीई), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), एक्सेस उपकरण, अन्य वायरलेस उपकरण और एंटरप्राइस इक्विपमेंट जैसे स्विच, राउटर इत्यादि सहित दूरसंचार उपकरण का विनिर्माण करना है।

(ख) दूरसंचार विभाग ने स्कीम की अवधि में 12,195 करोड़ रू. के वित्तीय परिव्यय के साथ भारत में डिजाइन आधारित विनिर्माण सहित नेटवर्किंग उत्पादों और दूरसंचार को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 24.02.2021 को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को अधिसूचित किया है। इस स्कीम के तहत 42 कंपनियों के लिए 11,508 करोड़ रू. की निधि की मंजूरी दी गई है। पीएलआई स्कीम के तहत तमिलनाडु में कंपनियों के लिए 902.87 करोड़ रू. की धनराशि को मंजूर किया गया है। तथापि असम और राजस्थान से किसी कंपनी ने पीएलआई स्कीम के तहत आवेदन नहीं किया है।

(ग) दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए पीएलआई स्कीम के तहत इन 42 कंपनियों ने 4,115 करोड़ रू. का निवेश, 2.45 लाख करोड़ रू. की अतिरिक्त बिक्री और स्कीम की अवधि तक 44,000 से अधिक के रोजगार सृजन की प्रतिबद्धता की। इन लक्ष्यों की तुलना में 1 अप्रैल, 2021 से 31 अक्टूबर, 2022 तक 952 करोड़ रू. का संचयी निवेश, 16,313 करोड़ रू. की बिक्री और 11,847 रोजगार की उपलब्धि हासिल हुई है।

दूरसंचार विभाग की आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत एन्ड-टू-एन्ड स्वदेशी रूप से विकसित दूरसंचार प्रौद्योगिकी उत्पादों को स्थापित करने का लक्ष्य है। सरकार और भारतीय उद्योग के सदस्यों के प्रयासों से भारत संचार नेटवर्क लिमिटेड वाणिज्यिक नेटवर्क में तैनाती हेतु स्वदेशी 4जी स्टैक को विकसित किया जा सका है। इसके अलावा 5जी के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के उद्देश्य से दूरसंचार विभाग ने डिजाइन-आधारित विनिर्माण के तहत 17 कंपनियों को मंजूरी दी है।

(घ) और (ड.) ओपन आरएएन अनुरूप 5जी उपकरण के विकास हेतु विभिन्न भारतीय स्टार्ट-अप और एमएसएमई के सहयोग के लिए सेन्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स (सी-डॉट) द्वारा 5जी एलायंस और आईओटी नवाचार केन्द्र शुरू किया गया है।

****